

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक: 3 / अगस्त, 2018

विषय :- नाबार्ड की RIDF-XXI योजनान्तर्गत(फेस-1) वित्त पोषित पेयजल योजनाओं हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1 कैम्प देहरादून दिनांक 10 अगस्त, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड की RIDF-XXI योजनान्तर्गत वित्त पोषित 13 पेयजल योजनाओं हेतु संलग्न सूची में वर्णित योजनाओं के सम्मुख कालम-6 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 2571.20 लाख (रू0 पच्चीस करोड एकहतर लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।
- (ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।
- (iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।
- (iv) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं व कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (v) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भौति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- (vi) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (vii) शासनादेश संख्या-642/उन्तीस(2)/16-2(42 पे0)/2015 दिनांक 28 अप्रैल, 2016 के अनुरूप शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-13, लेखाशीर्षक- 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01- जलापूर्ति- 102-ग्रामीण जलपूर्ति -98-नाबार्ड वित्त पोषित -01-नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं हेतु अनुदान (4215-01-102-05से स्थान्तरित)-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या- H 1808131674 दिनांक 30 अगस्त, 2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या- 519/3(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)/ XXVII
(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)

अपर सचिव।

पृ० संख्या-2075(1)/उत्तीस(2)/18-2(42 पे०)/2015, तददिनांकित।
प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून।
4. निदेशक, एन.आई.सी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. सहायक महाप्रबन्धक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, होटल सनराईज विल्डिंग,
113/2, राजपुर रोड़, देहरादून।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
8. बजट निदेशालय, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग- /2, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।